



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 24, 1988/अब्रहयण 3, 1910
No. 614] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 1988/A BRAHAYANA 3, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given for this Part in order that it may be filed as
separate compilation

कार्यालय: लोक-शिक्षण तथा पेशा मंत्रालय

(कार्यक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1988

अधिसूचना

क्र. सं. 1100(अ)—केंद्रीय सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के
क्यों निश्चित मामले की, अर्थात्, तमिलनाडु में चीनी कारखानों से गन्ना शीरा की

बड़ी मात्राओं का परिशोधित स्पिरिट और पेय ऐल्कोहॉल में परिवर्तन करने के लिए अप्रयोज्य की, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के राजकोष में राजस्व की भारी हानि हुई है, जून, 1974 से आगे की अवधि के दौरान तमिलनाडु राज्य में और उससे केरल राज्य को और केरल राज्य में परिशोधित स्पिरिट की बड़ी मात्राओं के ओर अनुज्ञात मात्राओं से अधिक मात्राओं के अवैध संचलन की, तथा उससे संबंधित अभिकथित भ्रष्ट आचरणों को जांच करने के लिए, एक सदस्य, अर्थात्, उड़ीसा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति श्री एस. के. रेगुमिलकर बने जांच आयोग का अस्तित्वशील रहना सब और आवश्यक नहीं है।

2. अतः केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) का धारा 7 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राज्यपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त आयोग अस्तित्वशील हो जाएगा और श्री एस. के. रेगुमिलकर के सदस्य के पद पर भर्ती रहेंगे।

[संख्या 375/11/81-ए.बो.डी. (IV)]

श्रीमती वी. वन. पंडुनत सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 24th November, 1988

NOTIFICATION

S.O. 1100(E).—Whereas the Central Government is of opinion that the continued existence of the Commission of Inquiry consisting of a single member namely, Shri S. K. Ray, retired Chief Justice of Orissa High Court, which was appointed under the notification of Government of India in the late Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms) No S.O. 488(E) dated the 10th June, 1981, to enquire into a definite matter of public importance, namely, diversion of large quantities of sugarcane molasses from sugar factories in Tamil Nadu for conversion into rectified spirit and potable alcohol, resulting in huge loss of revenue to the State exchequer, the illegal movement during the period from June, 1979 onwards, of huge quantities of rectified spirit, and in excess of the permitted quantities, in and from the State of Tamil Nadu to and in the State of Kerala, and the alleged corrupt practice relating thereto, is no longer necessary,

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby declares that the said Commission shall cease to exist and Shri S. K. Ray shall cease to hold the office of the Member of the said Commission on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[H. No. 375/11/81-AVD.IV]

SMT. B. SEN, Jt. Secy.

